संपादकीय

सत्य निकेतन का हादसाः विकास की कीमत आखिर कब तक?

दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत का अचानक ढह जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं, बल्कि हमारी शहरी व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। रविवार को हुई इस घटना में लोगों के मलबे में दबने की सूचना के बाद राहत और बचाव दलों ने युद्धस्तर पर अभियान चलाया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुछ लोगों की मौत की खबर ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। हर ऐसी घटना के बाद कुछ घंटों के लिए प्रशासन सक्रिय होता है, बयान जारी होते हैं और जांच के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्था का उद्देश्य केवल हादसे के बाद राहत पहुंचाना है या हादसे को होने से रोकना भी है?

दिल्ली जैसे महानगर में जहां हर वर्ष हजारों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं, वहां सुरक्षित आवास सबसे बुनियादी आवश्यकता है। सत्य निकेतन जैसे छात्र बहुल इलाकों में भवनों का उपयोग बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और किरायेदारों के रहने के लिए होता है। ऐसे में भवन की मजबूती, अग्नि सुरक्षा, अवैध निर्माण और समय-समय पर संरचनात्मक जांच को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही सीधे मानव जीवन को खतरे में डालती है। इस हादसे की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि भवन की संरचनात्मक स्थिति कैसी थी, वहां किसी प्रकार का निर्माण या मरम्मत कार्य चल रहा था या नहीं, आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं और संबंधित विभागों ने समय रहते निरीक्षण किया था या नहीं। यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी में केवल एक इमारत की जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा। दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में पुरानी, जर्जर और अनधिकृत इमारतों का व्यापक सर्वे होना चाहिए। खासकर उन भवनों की, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मजदूर या किरायेदार रहते हैं। सरकार और स्थानीय निकायों को तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भवनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। खतरनाक इमारतों की पहचान कर वहां रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही निरीक्षण और अनुमति देने वाली व्यवस्था में भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सत्य निकेतन की घटना हमें यह याद दिलाती है कि इमारतें केवल ईंट, सीमेंट और लोहे से नहीं बनतीं; उनमें लोगों की जिंदगी बसती है। इसलिए विकास की दौड़ में सुरक्षा को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अब समय है कि हर बड़े हादसे के बाद शोक व्यक्त करने की परंपरा से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें हादसे होने से पहले खतरे की पहचान हो। किसी परिवार को अपने प्रियजन को केवल इसलिए न खोना पड़े कि किसी भवन की सुरक्षा जांच समय पर नहीं हुई। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इमारत क्यों गिरी; असली सवाल यह है कि अगली इमारत गिरने से पहले हम क्या करेंगे?

विनोद शर्मा, संपादक

रास्ते अब मंजिल तक नहीं, जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति से भी जोड़ेंगे

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

रास्ते अब मंजिल तक नहीं, जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति से भी जोड़ेंगे। सड़कें किसी देश की केवल राहें नहीं, उसके विकास की दिशा भी बताती हैं। भारत में ये अब शहरों और बाजारों को जोड़ने वाले रास्ते भर नहीं रहीं, बल्कि बदलती विकास-दृष्टि की पहचान बन रही हैं। एनएचएआई की 'आरोग्य वन' पहल के तहत राजमार्गों के दोनों ओर नीम, आंवला, जामुन, इमली जैसी औषधीय वृक्ष प्रजातियाँ (और उपयुक्त स्थानों पर तुलसी, अश्वगंधा जैसी वनस्पतियाँ) कतारों में दिखें, तो यह केवल सड़क-सौंदर्य नहीं होगा। यह उस समझ का संकेत होगा कि तेज रफ्तार विकास को भी अंततः हवा, पानी और हरियाली की जरूरत है। सड़क किनारे खड़ा एक छोटा पौधा इसलिए मामूली नहीं–वह उस सोच का प्रतीक है, जिसमें विकास प्रकृति को पीछे छोड़कर नहीं, साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है।

इसे सिर्फ हरियाली की सरकारी कवायद मानना, इसके भीतर छिपे बड़े अर्थ को अनदेखा करना होगा। सड़क किनारे औषधीय पौधों की कतारें एक ऐसी मौन स्वास्थ्य-पट्टी बन सकती हैं, जो बिना कुछ कहे यात्री के मन तक पहुंचे। लंबी यात्रा में धूल, धुआं, शोर और तनाव के बीच तुलसी की सुगंध, नीम की छाया या आंवला-जामुन की हरियाली मन को ठहरने का अहसास दे सकती है। साथ ही, ये पौधे प्रकृति के उस पुराने ज्ञान की याद दिलाएंगे, जिसे आधुनिक जीवन सुविधा की दौड़ में पीछे छोड़ आया है। एक ओर वे कार्बन सोखकर हवा को बेहतर बनाएंगे, दूसरी ओर आयुर्वेद की परंपरा को आधुनिक राजमार्गों से जोड़ेंगे। सड़क और स्वास्थ्य का यह संगम विकास को थोड़ा और मानवीय बना सकता है।

किसी योजना की उम्र उसके उद्घाटन से नहीं, उसके निभाए जाने से तय होती है। 'आरोग्य वन' जैसी पहल तभी सचमुच जीवित रहेगी, जब सरकारी फाइलों से निकलकर स्थानीय समाज की जिम्मेदारी बने। राजमार्ग प्राधिकरण अकेले इसे नहीं संभाल सकता; स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाएं, आयुष व वन विभाग और प्रशासन को साथ आना होगा। किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती अतिरिक्त आमदनी का द्वार खोल सकती है। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को इनके संरक्षण और पहचान से जोड़ने पर पर्यावरण शिक्षा किताबों से निकलकर मिट्टी तक पहुंचेगी। तब पौधा किसी सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं, गांव, किसान, विद्यार्थी और यात्री–सबकी साझा जिम्मेदारी बनेगा।

बड़ी योजनाएं जमीन पर उतरने वाले कदमों से आकार लेती हैं। एनएचएआई की मौजूदा योजना में पहले चरण में टोल प्लाजा और विश्राम स्थलों के पास चुनिंदा भूखंडों पर रोपण हो रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एनएमपीबी) और आयुष मंत्रालय के अनुभव से हरियाली के साथ औषधीय संसाधन भी तैयार किए जाएं। मॉडल जोन और सेंसर-आधारित सिंचाई उपयोगी हैं, लेकिन सूखे क्षेत्रों में पानी और रखरखाव जरूरी है। स्थानीय वैद्य और आयुर्वेद विशेषज्ञ क्षेत्रानुकूल प्रजातियां तय करें। कच्चे माल को स्थानीय फार्मेसियों और आयुष केंद्रों से जोड़ा जाए। विश्राम स्थलों पर सूचना-पट्ट लगें, ताकि यात्री पौधों का औषधीय महत्व जानें। तब सड़क सफर के साथ ज्ञान का रास्ता भी बनेगी।

> राजमार्गों के किनारे पड़ी जमीन विकास की उस कहानी का अनकहा हिस्सा है, जिसे अक्सर कोई पढ़ता ही नहीं। धूल, तपिश, अतिक्रमण और प्रदूषण ने इन पट्टियों को उपेक्षा का भूगोल बना दिया है। औषधीय पौधों की योजनाबद्ध कतारें इसी भूले हुए भूभाग में फिर जीवन भर सकती हैं। घनी हरियाली धूल थामने, तापमान संतुलित करने और मिट्टी बचाने में मदद करेगी। साथ ही, यही वनस्पति पक्षियों, तितलियों और छोटे जीवों के लिए छोटे-छोटे आश्रय रचेगी। तब राजमार्ग केवल पहियों का गलियारा नहीं रहेगा; वह जैव-विविधता की जीवन-पट्टी भी बन सकेगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे हरित गलियारे भविष्य की पर्यावरण नीति का अहम आधार बन सकते हैं। हरियाली का अर्थ तब खुलता है, जब वह जीवन को छूने लगे।

[राजमार्गों के किनारे बोया जा रहा है सेहत और प्रकृति का भविष्य]
[राजमार्गों की खाली जमीन अब देश के स्वास्थ्य की जमीन बनेगी]

राजमार्गों के किनारे पड़ी जमीन विकास की उस कहानी का अनकहा हिस्सा है, जिसे अक्सर कोई पढ़ता ही नहीं। धूल, तपिश, अतिक्रमण और प्रदूषण ने इन पट्टियों को उपेक्षा का भूगोल बना दिया है। औषधीय पौधों की योजनाबद्ध कतारें इसी भूले हुए भूभाग में फिर जीवन भर सकती हैं। घनी हरियाली धूल थामने, तापमान संतुलित करने और मिट्टी बचाने में मदद करेगी। साथ ही, यही वनस्पति पक्षियों, तितलियों और छोटे जीवों के लिए छोटे-छोटे आश्रय रचेगी। तब राजमार्ग केवल पहियों का गलियारा नहीं रहेगा; वह जैव-विविधता की जीवन-पट्टी भी बन सकेगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे हरित गलियारे भविष्य की पर्यावरण नीति का अहम आधार बन सकते हैं। हरियाली का अर्थ तब खुलता है, जब वह जीवन को छूने लगे। इस योजना का महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य है। आधुनिक जीवन ने बीमारी का नया भूगोल रचा है–तनाव, प्रदूषण और बिगड़ती जीवनशैली उसका हिस्सा हैं। ऐसे में औषधीय वनस्पतियों को सजावटी हरियाली मानना भूल होगी।

वैज्ञानिक संरक्षण, कटाई और प्रसंस्करण से इनकी सामग्री सस्ती स्वास्थ्य-उपयोगों तक पहुंच सकती है। हालांकि राजमार्ग किनारे प्रदूषण (धूल, वाहन उत्सर्जन) से औषधीय गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए कटाई-उपयोग से पहले वैज्ञानिक परीक्षण जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं दूर हैं, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय वनस्पतियां सहायक हो सकती हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है–हर औषधीय पौधा हर व्यक्ति का उपचार नहीं। सही पहचान, वैज्ञानिक परीक्षण और विशेषज्ञ सलाह से ही इसकी संभावना जनहित में बदली जा सकती है।

हर पौधा लग जाने से हरियाली नहीं बनती; उसकी सांसें बची रहें, तभी प्रयास सार्थक है। यही इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी योजनाओं में पौधों की संख्या गिनना आसान है, उनकी जीवित रहने की दर गिनना असली प्रशासनिक कसौटी है। इसलिए सफलता का पैमाना 'कितने पौधे लगाए' नहीं, बल्कि 'कितने बचे, कितने बढ़े और कितना उपयोगी हुए' होना चाहिए। राजमार्ग प्राधिकरण, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन हो और नष्ट पौधों का पुनरोपण सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय लोगों को संरक्षण से जोड़ने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलें। जवाबदेही जितनी साफ होगी, योजना उतनी ही कागज से निकलकर जमीन पर जड़ पकड़ेगी। सड़कें जब केवल दूरी नहीं, देश की सोच भी तय करने लगें, तभी विकास का अर्थ व्यापक होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर औषधीय पौधों की पहल इसी बदलती सोच की अभिव्यक्ति है। राजमार्ग देश की धमनियां हैं तो उनके किनारे उगती हरियाली प्रकृति, स्वास्थ्य और समाज के बीच जीवंत सेतु बन सकती है।

कॅरियर की अंधी दौड़ में हांफती युवा पीढ़ी!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारे सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। वे बेहतर सहायक से ज्यादा तनाव के वाहक हैं। युवाओं में एआई के कारण नौकरियां जाने और खुद के अप्रासंगिक हो जाने का भय बैठ गया है। वे इस पूरे दृश्य को बहुत चिंता से देख रहे हैं। री-स्किलिंग का दबाव उन्हें गहरे भय में डाल रहा है। भारत युवाओं का देश है। जाहिर है ऐसे देश की चिंताएं बहुत अलग होती हैं। उसकी ज्यादातर आबादी को शिक्षा, रोजगार और सुंदर जीवन की कामना होती है। उनकी महत्वाकाक्षाएं, अवसरों की होड़ और दौड़। पाने की खुशी और न मिलने का आक्रोश सब साझा होते हैं। करियर में सफल होने, जल्दी और ज्यादा पाने की कामनाएं इस दौर का मूल्य हैं। ऐसे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को गहरी चुनौती है। संकट के बादल गहरे हैं। समाधान के सूत्र न्यूनतम।

बदलती कार्य संस्कृतिः सरकारों में नौकरियों के दरवाजे सिकुड़ रहे हैं। ज्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्रों में ही हैं। नौ से पांच बजे की पक्की नौकरियां अब स्वप्न ही हैं। उनकी जगह गिग इकोनामी (फ्री लांस, काट्रैक्ट वर्क) ने ले ली है। आर्थिक स्वतंत्रता की तो छोड़िए यह माडल भविष्य की अनिश्चितता और वित्तीय अस्थिरता भी ला रहा है, जिसके नाते बढ़ता मानसिक तनाव और अवसाद संकट को गहरा कर रहा है। हिंदुस्तान अलग तरह से चलता रहा है। परिवार इसकी प्राणवायु रहे हैं। परिवार का कोई एक आदमी नौकरी पर रहता था, शेष अपने घर-इलाके-गांव में बैठकर स्थानीय स्तर पर जो कर सकते थे करते थे। परिवार की छाया में सुरक्षा थी, संरक्षण था, बच्चों को संस्कारित करने के पारिवारिक उपक्रम थे। नई व्यवस्था ने एक परिवार में कई परिवार खड़े कर दिए हैं। इससे एक की जगह अब चार परिवार, चार चूल्हे और चार व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही है। आप कितना भी कमा रहे हैं वह कम ही है। इसने नई पीढ़ी को ईएमआई के दुष्चक्र में फंसा कर नई व्यवस्थाओं का गुलाम बना दिया है। परिवार व्यवस्था भारत की संस्कृति का आधार रही है। वह संस्कारशाला भी है।

कार्य और जीवन का संतुलनः कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारे सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। वे बेहतर सहायक से ज्यादा तनाव के वाहक हैं। युवाओं में एआई के कारण नौकरियां जाने और खुद के अप्रासंगिक हो जाने का भय बैठ गया है। वे इस पूरे दृश्य को बहुत चिंता से देख रहे हैं। री-स्किलिंग का दबाव उन्हें गहरे भय में डाल रहा है। इससे मानसिक थकान होना स्वाभाविक ही है। इस समय सबसे बड़ी चिंता कार्य और जीवन संतुलन की है। वर्क फ्राम होम और डिजिटल कनेक्टिविटी ने सारा कुछ बदलकर रख दिया है। काम के घंटे अब प्रायः 24 घंटे ही हैं। देर रात तक ई-मेल, रिर्पोट्स और मैसेज का जवाब देते हुए युवा 'आलवेज आन' मोड में रहते हैं। जिससे पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत समय और नींद सब प्रभावित हो रही है। बर्नआउट की बढ़ती दर, काम के अनिश्चित घंटे, स्पर्धा का वातावरण और टारगेट पूरे करने का दबाव साथ चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) ने बर्नआउट को प्रोफेशनल बीमारी मान लिया है। यह अब भारतीय कारपोरेट जगत में एक अनिवार्य समस्या बन गयी है।

सोशल मीडिया से बनती छवियांः सोशल मीडिया ने समाज में अलग तरह की स्पर्धा की छवियां प्रस्तुत की हैं। अपने सुखद, आनंद के क्षणों को वायरल करने की बीमारी दूसरे की पीड़ा का कारण बन जाती है। किसी की बड़ी पदस्थापना, उसकी पार्टियां, रील्स, पर्यटन की तस्वीरें, महंगी जीवनशैली का विज्ञापन करना, सफलताओं के हाईलाइट्स देखकर तुलना और स्पर्धा की बातें तेज होती हैं। इससे हीनभावना और तनाव का जन्म भी होता है। परिजन और बच्चे भी अपने पालकों से ऐसी ही जीवन शैली की अपेक्षा करते हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए तनाव प्रबंधन की विधियां समझने और उन्हें जीवन की ठोस सच्चाइयों से जोड़ने की जरूरत है। योग, ध्यान के अनेक अभ्यास जीवन में शांति ला सकते हैं। जिंदगी के हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं। रील्स की तुरंतवादी जीवनशैली और जीवन के सतत संघर्ष को समझने की जरुरत है।सोशल मीडिया से प्रक्षेपित हो रही छवियों से प्रभावित होने के बजाए, लोगों के संघर्ष और उससे उपजी सफलताओं के पाठ भी पढ़े जाने चाहिए।

गुरु वंदन कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों का सम्मान

शिक्षक केवल विद्यार्थियों का भविष्य नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैंः महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर नगर निगम कार्यालय सभागृह में गुरु वंदन कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रमुखों का महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव द्वारा शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों के लिए स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई।

गुरु का सम्मान हमारी संस्कृति और संस्कार की पहचान : महापौर अमृता अमर यादव

इस अवसर पर महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि 'गुरु केवल ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के भीतर ज्ञान के साथ संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षक समाज और राष्ट्र के भविष्य के वास्तविक निर्माता हैं।'

महापौर ने कहा कि 'हमारे बच्चे और युवा खंडवा के आने वाले कल की तस्वीर हैं। उनके व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने में माता-पिता के साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक निभाते हैं। एक शिक्षक का दिया हुआ ज्ञान और संस्कार विद्यार्थी के जीवन के साथ-साथ उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। 'उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु वंदन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके योगदान को नमन करने का अवसर है। आज नगर निगम द्वारा शहर के शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का सम्मान कर शिक्षा जगत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जा रही है। महापौर ने कहा कि 'नगर निगम क्षेत्र के विकास के साथ-साथ शिक्षा, संस्कार और नई पीढ़ी के निर्माण को भी हम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हैं। शहर के शिक्षक जिस समर्पण और निष्ठा के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को संवार रहे हैं, वह वास्तव में अभिनंदनीय है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर खंडवा के सभी गुरुजनों को नमन करते हुए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूं।'

छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

» **राहुल गांधी जी की 'छात्रों की गूंज' को लेकर छात्रों में काफी उत्साह, बड़े उत्साह के साथ युवा कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन 'उत्तमपाल सिंह'**

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

इंदौर में 19 सितंबर 2026 शनिवार को आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जिले से अधिक से अधिक छात्रों एवं युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को गांधी भवन में जिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई।

जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि दोपहर 4 बजे हुई बैठक जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह एवं हरसूद विधानसभा प्रभारी राजेन्द्र रघुवंशी के नेतृत्व में आयोजित की गई। संचालन धर्मेन्द्र सिंह राठौर ने किया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई तथा जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में छात्रों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ें और इंदौर में होने वाले आयोजन में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बारकोड से रजिस्ट्रेशन करवाये।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। 8 सितंबर को ओंकारेश्वर में सुबह 11 बजे, पुनासा में दोपहर 1 बजे, मुंदी में 3 बजे और खंडवा ग्रामीण में शाम 5 बजे बैठक कर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। 9 सितंबर को छनेरा में सुबह 11 बजे तथा खालवा में दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित होगी। 10 सितंबर को छैगांवमाखन में सुबह 11 बजे, पंधाना में दोपहर 1 बजे और सिंगोट में शाम 4 बजे बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि खंडवा से लगभग 10000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन का टारगेट तय किया गया है, हमारी कोशिश रहेगी कि इससे अधिक रजिस्ट्रेशन किया जावे।

गांधी भवन में आयोजित बैठक में सुरेश पवार, कैलाश हरि पटेल, बसंत पवार, प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, संजीव पटेल, सरोज बघेल, रूपा कास्डे, अनिल जाधव, पवन पाटीदार, गिरवर सिंह राजपूत, जयेश पटेल, शैलेन्द्र सिंह तोमर, जयेंद्र सिंह तोमर, नादान सिंह, मितेश देसाई, प्रियेश चौकड़े, मोंटी सिंह पंवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद म.प्र. पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर ने किया खण्डवा में पुलिस बटालियन हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

विकास की बात भाजपा के साथ ही हो सकती है, भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है, देर हे लेकिन अंधेर नहीं, वर्षो से सुरक्षा की दृष्टि से एवं त्योहारो को व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुरूप बटालियन के लिए जिला प्रशासन द्वारा वर्षो पूर्व सुरगांव निपानी में लगभग 105 एकड़ भूमि बटालियन हेतु सुरक्षित की गई थी। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि विगत दिनों खंडवा प्रवास पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंच के माध्यम से उपस्थित जनों के बीच यह घोषणा की थी बटालियन की स्थापना खंडवा में ही की जाएगी, साथ ही खंडवा मुंदी मार्ग की भी स्वीकृति की घोषणा की थी।

प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि खंडवा में बटालियन को लेकर मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तंनवे, महापौर अमृता अमर यादव लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर खंडवा में बटालियन खोलने की मांग करते रहे, इसके परिणाम स्वरूप बटालियन की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। उल्लेखनीय की विधानसभा में भी खंडवा विधायक कंचन तंनवे द्वारा बटालियन को लेकर अपनी बात रखी गई थी जिसका समर्थन विधानसभा में ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री श्री शाह ने किया था। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव म.प्र.की खण्डवा में पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किये जाने हेतु पुलिस बटालियन हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण म.प्र.पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर जी.पी. पतोड़ द्वारा अपनी टीम के साथ किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) गजेन्द्र सिंह कंवर एवं रक्षित निरिक्षक शिव मंगल सिंह उपस्थित रहे।

वार्ड 34 उपचुनावः कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, आज गांधी भवन में बनेगी रणनीति

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही खंडवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34, रानी दुर्गावती वार्ड में रिक्त पार्षद पद के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के तत्काल बाद कांग्रेस संगठन ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। वार्ड में मजबूत संगठनात्मक तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहर) प्रतिभा रघुवंशी ने बताया कि प्रत्याशी चयन, चुनाव संचालन एवं आगामी रणनीति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसजनों की महत्वपूर्ण बैठक आज 7 सितंबर सोमवार को दोपहर 2:30 बजे गांधी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से सुझाव लेकर चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन सुबह 10:30 बजे से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की जांच 16 सितंबर को होगी। 18 सितंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी तथा इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वार्ड 34 में 29 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059